

विचार बिन्दु

चरित्र वृक्ष है और प्रतिष्ठा उसकी छाया। –अब्राहम लिंकन

भविष्य की नींव हम कैसी निर्माण कर रहे है?

कृषि व प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकारों अभी तक देश के आधे युवाओं को वंचित करती रही है विभिन्न कारणों और बिना कारणों के :

कृषि व प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र मेंप्रदेश सरकारें अभी तक देश केआधे युवाओं को वंचित करती रही है विभिन्न कारणों और बिना कारणों के : स्वतंत्रता पश्चात देश की सरकार मंचों से जनता को अभी तक ध्र्मित और गुमराह ही करती रही है। सभी प्रकार की शिक्षाओं के अनुपयुक्त संसाधन और उनके लचर पचर सञ्चालन ने देश में कतिपय शिक्षाओं को छोड़कर लगभग सभी प्रोफेशनल जिसमे कृषि शिक्षा भी शामिल है ,सरकार के लगातार वर्ष दर वर्ष उदासीन रवैये ने शिक्षण संस्थाओं के भवनों को तो बर्खा दिया है परन्तु उनमें होने वाली सभी शिक्षण गतिविधियों का ऐसा सत्य नाश मारा है जो मेरे आंकलन से अगले तीन दशकों तक भी सुचारु और वांछित राह पर आने वाली नहीं।

इस लेख में पाठकों ,छात्रों ,अभिवावकों एवं उन बुद्धि जीवियों और सरकार में गुना भाग करने वाले सचिवो का ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा जो शिक्षा के सञ्चालन को सर्वोत्तम श्रेय देते हैं। सरकारी विफलताओं से उपजी त्रुटि शिक्षण में व्याप्त होकर छात्रों का अहित और अंत: देश का अहित करती है ,उनपर अपने कुछ प्रश्न उठाकर प्रभावित वर्ग से ही उनका उत्तर देने काअनु रोध करता हूँ,कियौंकि देश जाय भाड में ,छात्रों का समय और उन के अभिवावकों का असीम धन का जब अबव्यय होता है उसकी भरपाई कभी संभव नहीं होपाती। भविष्य में धन भले ही उपलब्ध कर लिया जाय बोता समय और छात्र की बीती आयु की भरपाई सरकार अथवा अन्य किसी के माध्यम से तीन पीढियों भी क्षितपूर्ति नहीं कर सकेँगी।

जनप्रतिनिधि एक निश्चित समय के बाद राजनीत से चले ही जाते है। सरकारी अफसर भी रिटायर होकर अपने घर बैठे पेंशन लें रहे होते है लेकिन पढने वाले का समय जो बिना पढे बीत गया वो क्या लौट सकेगा ? पढने वाला भी पढने की आयु सीमा पार कर जायेगा और अन्य किसी काम का फिर नहीं रहेगा। सियाय मजदूरी करने को क्या प्रधान मंत्री ,शिक्षा मंत्री व् अन्य कोई इस प्रश्न का जवाब देश को दे सकता है ?

दूसरा प्रश्न देश के युवा को अन्य देशों में पढाई के लिए क्यों जाना पढता है ?कारण स्पष्ट है देश की सरकारों ने छात्रों की अपार सख्त्य और बढ़ते तकनीकी व् प्रोफेशनल ज्ञान के पाने के लिए देश का युवा लालायत है लेकिन सरकार के बोये अनेक उपजे अवरोधों से न तो उसे वांछित संस्था में प्रवेश मिलता है और न वांछित विषय। कोई राह न मिलते देख वह और उसके अविभावक अपने संपति बेवकर अपने लालछे को किसी अन्य देश में बिना सरकारी निर्देशएवं मदद के बिचौलितियों

सरकार के लगातार वर्ष दर वर्ष उदासीन रवैये

ने शिक्षण संस्थाओं के भवनों को तो बर्खा दिया

है परन्तु उनमें होने वाली सभी शिक्षण

गतिविधियों का ऐसा सत्य नाश मारा है जो मेरे

आंकलन से अगले तीन दशकों तक भी सुचारु

और वांछित राह पर आने वाली नहीं।

प्रधान मंत्री ने अपने चार पांच मंत्रिओं को यूक्रेन ,पोलैंड ,रूस आदि देशों में उन छा त्रों को निकालने और वापिस देश लाने तो भेजा। लौट कर वे सब मंत्री ,प्रधान मंत्री और छात्र चुप बैठ गए वहां जो कुछ पडा सब बेकार। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि इन छात्रों के लिये वांछित शिक्षा देश में ही क्यों उपलब्ध नहीं हो सकती ? सात दसक बीत गए अनेक पांच वर्षीय योजनाएं पूरी होचुकी ,फिर भी देश का युवा न तो शिक्षित हो सका और न ही संस्था योजनाओं का सही क्रियान्वन नहीं हुआ ,सत्ता में बैठे राजनेता और उनके विचौलिये देश का जो धन विकास में खर्च होंना चाहिये था उसको डकारते रहे और महल बनाकर उनके कमरे कॅंसी नोटों की गड़्डियों से भरते रहे। प्रधान मंत्री मोदी जी वैसे तो ईमानदार है परन्तु भ्रष्ट लोगों पर आज तक न तो नकैल कसी जा सकीऔर न ही कोई अन्य वांछित कार्यवाही की गयी। भाषण में किसी बात को यदा कदा मंच से पब्लिक में कह देना और वासवब में उस पर कार्यवाही को आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने से उनकी प्रतिभा में इजाफा हुआ या नहीं ? उनके अंदर अन्य कोई विकार तो घर नहीं कर गया ? इस लेख से मेरा मकसद है कि देश केसभी युवाओं को वांछित शिक्षा और उद्यम के समान अवसर उपलब्ध हों। शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित न किया जाय भले ही सीटें व् अन्य संसाधन बढ़ाने पडें। अभी ईरान से भारत के छात्रों को लेकर तीन हवाई ट्रिप दिल्ली आ चुकी है. लेकिन सरकार फिर भी शर्मिदा नहीं ? कि भारत यूक्रेन ,ईरान ,पोलैंड सरीखे देशों से भी शिक्षा में पिछडा है। फिर हम किस आधार पर विकसित और चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था की डींग मारते है ? . प्रतीत होता है हमारी हर विवेक किसी ने गिरवी रख लिया है ? यदि ऐसा है तो फिर सरकार भेड़ों के रेवडों को चरा रही है। इससे अधिक कुछ नहीं। देश के प्रधान मंत्री वर्तमान आरक्षण को कभी समाप्त नहीं करने के घोषणा पहले ही कर चुके है लेकिन शेष युवा और वे जो येन केनो कि विदेश जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं ,के लिएप्रधान मंत्री और उनकी सरकार के पास कोईयोजना है ?हो तो उजागर करें। शेष आधी युवा पीढी वर्ष दर वर्ष अपनी प्रतिभा कुंठित कर अपराध जात की राह पकड़ने में संकोच नहीं करेगी ? मध्यप्रदेश के बीहड़ों में पनपे डाकुओं का भी इतहास भी ऐसा ही है। परतु अब कोई विनोबाभाव सरीखे व्यक्ति मिलने वाले नहीं। मार्गदर्शक जयप्रकाश बाबू जैसे भी अब नहीं मिलता।

वांछित पढाने वाले की जगह ठेके परअनुभवहीन इस कार्य के लिए उच्च शिक्षा में नियुक्त कर लिए जाते हैं। खाली पदों को संचिव लोग भरने नहीं देते और किसी प्रकार साक्षात्कार तक प्रक्रिया पहुँच भी जाय तो अपने ही किसी सेक्रेट्री से रस्टे करवा देते है। इससे जो अनुभवहीन पढा रहे है वे जाँब में चलते रहते है। यह खेल है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में कभी देखने को मिल जाता है। उच्च शिक्षा के इस खेल को आम आदमी समझ नहीं सकता।

मुख्य प्रश्न है कि रिक्त पद तुरंत क्यों नहीं भरे जाते ? इसलिए कि इसमें सबकी मिली भगत है और फायदा भी सब का छात्रों के अतिरिक्त। अंत में मैं अनुसंशा करता हूँ कि किसी भी युवा छात्र यदि वह वांछित योग्यता रखता है उसे किसी भी उपयुक्त विषय और महाविद्यालय में प्रवेश बिना किसी सीमा निर्धारण के दिया जाय ,यह उसका अधिकार है और उसे मिलना ही चाहिए भले ही आगे परीक्षा में वह असफल हो जाय। प्रवेश परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध लगा कर उनेह अमान्य घोषित किया जाय। अन्य देशों में देश का कोई युवा पढने के लिए जाने कोविवश न होदेश की आजादी पर यह कलंक है। इस संघर्ष में देहली स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जो देश में कृषि अनुसन्धान और उच्च शिक्षा को विभिन्न प्रकार से सपोर्ट और मार्गदर्शन करती है के कलापों पर भी दृष्टि डालना जरुरी है। यह परिषद् मूलत: कृषि अनुसन्धान के लिये बनी थी कालान्तर में इसने शिक्षा और प्रसार कार्यक्रमों को भी अपने परिधि में समेट लिया। फलस्वरूप विश्वविद्यालय उदासीन हो गए और उनकी अकादमिक कौंसिल पोस्ट टोड्युए कौंसिल ,कोर्स समिति आदि सभी एक्ट प्रदत्त प्रावधान निष्क्रिय हो गए।

परिषद् ने कृषि संकाय के सभी विषयों पर विस्तृत विवरण तैयार कर नेट पर अपलोड करवा दिया।सुविधा तो अच्छी थी लेकिन प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बंधित प्रबंधकों ने अनुचित लाभ उठाया। यह सुविधा परिषद् ने केवल गाइडेंस के लिए दी थी परन्तु इसका प्रभाव यह पडा कि छात्रों ने लाइब्रेरी को तिलांजलि दे दी ,टीचर्स ने भी उसे आधार मानकर सम्बंधित विषय वस्तु कक्षा में छात्रों को परोसना शुरू कर दिया यह देख छात्रों ने कक्षाओं में केवल हाज़िरी के लिए जाना ही जरुरी समझा कियौंकि विषय के विस्तृत नोट्स अब उनेह नेट पर पढने को मिल रहे है। अंततोगत्वा पढाने वाले टीचर्स की कमी भी अब कोई मायने नहीं रखती।

लोकलात बचाने के लिए महाविद्यालय ठेके पर विवरण करते बेरोजगारों को निर्मंत्रित कर उनेह मजदूरी पर कक्षा को पढाई की औपचारिकता सौंप देते हैं। इस प्रणाली से सरकार का अपार धन वर्षों से बच रहा है। प्रैक्टिकल के नाम पर नाम के लिए कोई एक दो परिक्षण लैब असिस्टेंट अथवा टेक्निकल सहायक करवा देता है।महाविद्यालयों और अधिस्तनात टीचर्स जो विषय पढा ते है वे किसी भी मान्य समिति से प्रमाणित नहीं होते।

यह प्रदेश सरकारों की कितनी उत्तम रिति है।पाठकों को बता दें कि कॉलेजो में दैनिक मजदूरी पर जो टीचर्स पढाते है वे किसी भी समिति से प्रमाणित नहीं होते। मैं एक प्रोफेशनल और लेखक की हैसियत से दावे से कहता हूँ कि स्नातक डेग्री के छात्र बारहवीं कृषि में कराये प्रैक्टिकल भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसी कृषि शिक्षा भविष्य में देश का क्या उत्थान करेगी और कृषि उन्नयन में कैसे भागीदार बनेगी ?यह आभी सोचने का विषय है कियौंकि लगभग 20 वर्ष का काल बीत गया इस स्थिति भी। समझ नहीं आता भविष्य की नीव हम कैसी निर्माण कर रहे है ?

अतिथी संपादक
प्रो. वीर बहादुर सिंह ,
पूर्व कुलपति व् अधिष्ठाता ,
महाराणा प्रताप कृषि
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ,उदयपुर

क्या शिक्षकों के चेहरे बदल गए हैं ?

शिक्षकों की स्थिति और चुनौतियां, शिक्षक अक्सर कई चुनौतियों का सामना करते हैं



अशोक कुमार

वर्तमान में शिक्षकों की भूमिका और उनका प्रशासन के प्रति रवैया एक जटिल विषय है, जिस पर अलग-अलग राय हो सकती है। यह कहना कि "शिक्षकों के चेहरे बदल गए हैं" और वे "केवल प्रशासन के गुणगान गाते रहते हैं" एक सामान्यीकरण हो सकता है, क्योंकि शिक्षकों के विचार

और व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं।

शिक्षकों की स्थिति और चुनौतियाँ शिक्षक अक्सर कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

सेवा शर्तें और वेतन: कई शिक्षकों को लगता है कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता और उनकी सेवा शर्तें भी संतोषजनक नहीं हैं, जिससे उनके मनोबल पर असर पड़ता है।

प्रशासनिक दबाव: स्कूलों और शिक्षा विभागों से आने वाले प्रशासनिक दबाव के कारण शिक्षकों को अक्सर पाठ्यक्रम पूरा करने और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप: शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ी चुनौती है, जिससे शिक्षकों की स्वायत्तता प्रभावित होती है।

कार्यभार: शिक्षकों पर शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ

अक्सर अधिक होता है, जिससे उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का समय नहीं मिलता।

विरोध या पक्ष न रखने के कारण शिक्षक अगर किसी नीति की बुराई या विरोध नहीं करते या अपना पक्ष नहीं रखते, तो इसके कई कारण हो सकते हैं:

डर और असुरक्षा: शिक्षकों को अक्सर यह डर होता है कि अगर वे प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्थानांतरण, पदोन्नति में बाधा या अन्य दंड।

पदानुक्रमित ढाँचा: भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक स्पष्ट पदानुक्रम है, जहाँ शिक्षकों को अक्सर उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है।

संघों की भूमिका: शिक्षक संघों की भूमिका कमजोर होने से भी

शिक्षकों को अपनी बात रखने में मुश्किलें आती हैं। कुछ संघ शायद अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने में उतने प्रभावी न हों।

नीतियों का अनुपालन: कई बार शिक्षक सिर्फ नीतियों का अनुपालन करते हैं, भले ही वे उनसे सहमत न हों, ताकि वे विवादों से बच सकें और अपनी नौकरी सुरक्षित रख सकें।

क्या सभी शिक्षक ऐसे हैं? यह कहना गलत होगा कि सभी शिक्षक केवल प्रशासन के गुणगान गाते हैं। आज भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे अपनी बात रखने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग करते हैं, जैसे: शिक्षक संघों के माध्यम से: कुछ शिक्षक संघ आज भी सक्रिय हैं और शिक्षकों के अधिकारों और नीतियों में सुधार के

लिए आवाज उठाते हैं।

अकादमिक मंचों पर: शिक्षक अक्सर सेमिनारों, सम्मेलनों और अकादमिक मंचों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं।

सोशल मीडिया: कुछ शिक्षक सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिक्षा नीतियों पर अपनी राय रखते हैं, हालांकि इसमें जोखिम हो सकता है।

यह सच है कि कुछ कारक उन्हें अपनी राय खुलकर व्यक्त करने से रोकते हैं। एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षकों को अपनी बात रखने और रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार मिलना चाहिए।

अशोक कुमार
पूर्व कुलपति कानपुर ,
गोरखपुर विश्वविद्यालय ,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में

जनसमस्याओं का समाधान

मकराना, (निस) उपखंड की जखली, भींचावा और काशीनगर ग्राम पंचायतों में शुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं का लाभ आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जखली शिविर का निरीक्षण करने के लिए डीडबाना-कुचामन के जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खटावत ने औचक निरीक्षण किया, उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित नोटिसों की तामील, पत्थरगाड़ी, सीमाज्ञान और नामांतरण से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वन विभाग ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत

■ भींचावा, काशीनगर ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित

पौधों का वितरण किया तथा पौधारोपण करवाया। खाद्य विभाग ने एनएफएसए के तहत लंबित प्रकरणों का समाधान किया, वहीं आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और नवीन पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय परिसरों की सफाई, अनुपयोगी व जर्जर सामग्री के निष्पादन, प्रवेशोत्सव का आयोजन, स्कूलों का क्रमोन्नयन, नए संकायों की शुरुआत तथा स्कूटी वितरण जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। ऊर्जा विभाग ने झूलते बिजली के तारों को व्यवस्थित किया और तारों के संपर्क में आने वाले पेड़ों की छंटाई की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल संसाधन विभाग ने लंबित जल कनेक्शन जारी किए, टंकियों की सफाई करवाई।

जोधपुर । किसी भी सरकार के सुशासन और नैतिकता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि वह सबसे पिछड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कर रही है। राजस्थान सरकार ने लगभग पिछले डेढ़ वर्ष में इस दिशा में अनेक प्रतिमान गढ़े हैं और इसकी ताजा कड़ी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। इस पखवाड़े के तहत जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत दहैजूर (पंचायत समिति केरू) में गुरुवार को आयोजित जनकल्याण शिविर में एक अनमोल क्षण तब देखने को मिला जब देसुरिया करवड निवासी गणेशाराम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर-कमलों से इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल प्राप्त हुई। गणेशाराम सुचता कुपलानी महाविद्यालय में बी.ए. तृतीय वर्ष का विद्यार्थी है, दोनों पैरों से दिव्यांग है। कॉलेज उसके गांव

से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्मे गणेशाराम के पिता वृद्ध हैं और परिवार की आजीविका का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। कॉलेज जाने के लिए उसे अब तक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त सहायता योजना के अंतर्गत दी गई है जिससे गणेशाराम के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। साइकिल प्राप्त करते हुए गणेशाराम की आँखों में जो चमक थी, उसने बता दिया कि यह सहायता उसके लिए केवल एक वाहन नहीं, बल्कि स्वावलंबन की सवारी है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा, सरकार का उद्देश्य

है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अक्षमता या संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गणेशाराम ने बताया, अब मुझे कॉलेज जाने में परेशानी नहीं होगी। मैं समय पर पहुंच सकूंगा, खुद अपने काम भी कर सकूंगा। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे गरीब और दिव्यांग छात्र के सपनों को उड़ान दी है। दहैजूर शिविर में इस तरह के कई संवेदनशील और जनकल्याणकारी क्षण देखने को मिले। गणेशाराम की मुस्कान ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार की योजनाएं जब सही हाथों तक पहुंचती हैं, तो वे सिर्फ लाभ नहीं, भविष्य गढ़ती हैं।

डॉ. मुखर्जी को राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता ने कांग्रेस पार्टी से अलग किया : मदन राठौड़

जयपुर/डीडबाना, । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को डीडबाना में आपातकाल की 50वीं बरसी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में कार्यक्रमीओं को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन एवं देशहित में किए गए उनके संघर्षों की चर्चा करते हुए कहा कि डॉ मुखर्जी असाधारण प्रतिभा, अद्वितीय मेधा के धनी थे। महज 32 वर्ष की आयु में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। 1935 में वे विधायक बने और 1936 में बंग-भंग आंदोलन के विरोध में उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उस समय बंगाल में हिंदुओं को उनके घरों से निकाल कर जबरन कब्जा किया गया, जिसका उन्होंने तीव्र विरोध किया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग ले गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के खिलाफ आवाज उठाई और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। डॉ. मुखर्जी ने सत्य और राष्ट्रिहत के लिए मंत्री पद त्याग दिया। उन्होंने बताया



डीडबाना में आपातकाल की 50वीं बरसी व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यक्रमीओं को संबोधित किया।

कि मुखर्जी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर जनसंघ की स्थापना की थी। पहले ही चुनाव में पार्टी ने 3 सांसद और 23 विधायक जीतकर राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक देश, एक विधान की भावना को लेकर वे मई 1953 को बिना परमिट कश्मीर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। राठौड़ ने आरोप लगाया कि उस समय की कांग्रेस

सरकार ने इस संदिग्ध मृत्यु की जांच तक नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन केवल ब्रिटिश नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की लालसा का भी नतीजा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आपातकाल को लोकतंत्र और संविधान की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू की गई इमर्जेंसी कांग्रेस द्वारा सत्ता की लालसा में की

गई तानाशाही का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान लाखों लोगों को रातों-रात गिरफ्तार किया गया, एस पर सेंसरशिप थोप दी गई, न्यायपालिका को कमजोर किया गया और लोगों की संपत्तियों तक पर मनमर्जी से कब्जा किया गया। राठौड़ ने 6 अगस्त 1975 को लागू हुए उस कानून का उल्लेख किया, जिसके तहत आपातकाल के खिलाफ कोई अपील तक नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 'संविधान बचाओ यात्रा' निकाल रही

■ इतिहास गवाह है आपातकाल लागू कर कांग्रेस पार्टी ने संविधान और जनता के अधिकारों को कुचलने का कृत्य किया :मदन राठौड़

है, जबकि इतिहास गवाह है कि इसी पार्टी ने संविधान और जनता के अधिकारों की सबसे बड़ी हत्या की थी। कार्यक्रम में राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आ न किया कि वे डॉ. मुखर्जी के बलिदान और आपातकाल के अत्याचारों को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चे इतिहास से परिचित रह सकें। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोषा, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, मान सिंह जी किसरिया, अशोक सैनी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नावों, मकराना, डीडबाना सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत-संस्कार किया।

	मेष घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मौलिक कार्य संभल हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	सिंह अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड़ रहेगी।
	वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।
	कन्या आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे।
	मिथुन आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा।
	कर्क मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनस्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य संभल हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	वृश्चिक वृद्धिक - नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक - आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	कुंभ विवादित मामलों में राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
	मीन परिवार में शुभ मांगलिक कार्यों संभल हो सकते हैं। आज समय में रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक-आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।